
Q. The depreciation of the rupee poses challenges for the Reserve Bank of India (RBI) in balancing inflation, growth, and currency stability. Analyze the policy options available to the RBI in addressing this situation

The depreciation of the Indian rupee poses significant challenges for the Reserve Bank of India (RBI) in maintaining a delicate balance between inflation control, economic growth, and currency stability. A weakening rupee increases import costs, fuels inflation, and raises external debt servicing burdens. At the same time, it enhances export competitiveness. The RBI, as the custodian of monetary stability, has multiple policy options to manage this situation effectively.

Policy Options Available to the RBI

1. Foreign Exchange Market Intervention

- **Direct Dollar Sales:** RBI can sell foreign exchange reserves to curb excessive volatility. For instance, in 2018, when the rupee breached the 74-mark against the US dollar due to rising crude oil prices, RBI intervened by selling dollars to stabilize the currency. However, frequent intervention can deplete forex reserves.
- **Buy-Sell Swap Mechanism:** Instead of directly selling dollars, RBI can use swaps, as seen in 2019, when it introduced a \$5 billion swap auction to manage liquidity while indirectly supporting the rupee.

2. Interest Rate Adjustments

- **Monetary Tightening:** Raising the repo rate can attract foreign capital inflows, strengthening the rupee. In 2013, during the 'Taper Tantrum' crisis, RBI raised interest rates to counter capital outflows and rupee depreciation. However, higher rates can slow down economic growth.
- **Maintaining a Neutral Stance:** If economic growth is a priority, RBI may avoid aggressive rate hikes, as seen in 2022 when it balanced inflation control with growth concerns amid global uncertainties.

3. Liquidity Management Measures

- **Open Market Operations (OMO):** RBI can conduct OMOs by selling government securities to absorb excess liquidity. For instance, in 2018, RBI used OMOs to curb inflationary pressures caused by a falling rupee.
- **Cash Reserve Ratio (CRR) Adjustments:** Raising CRR can help curb inflation but may tighten liquidity. In 2010, RBI increased CRR to control inflation, but it also impacted credit availability for businesses.

4. Boosting Capital Inflows

- **Encouraging FDI and FPI:** Easing restrictions and improving investor confidence can stabilize the rupee. In 2019, RBI and SEBI relaxed FPI norms, which helped attract investments and supported the rupee.
- **Monitoring External Commercial Borrowings (ECBs):** Regulating excessive foreign currency borrowings prevents currency mismatches. In 2013, RBI tightened ECB norms to curb external vulnerabilities.

5. Trade and Structural Reforms

- **Managing the Trade Deficit:** Reducing non-essential imports (such as gold restrictions in 2013) and boosting exports can help stabilize the rupee.
- **Incentivizing Export-Oriented Sectors:** The IT sector benefited from rupee depreciation in 2022, with companies like Infosys and TCS reporting higher revenue due to increased export earnings.

6. Allowing Market-Driven Adjustment

- **Letting the Rupee Adjust Naturally:** Allowing gradual depreciation can enhance export competitiveness. For example, in 2020, the RBI allowed the rupee to depreciate amid

COVID-19 disruptions to support exports. However, excessive depreciation can lead to inflationary pressures.

The depreciation of the rupee presents a complex challenge for the RBI, requiring a careful balance between inflation control, economic growth, and currency stability. While foreign exchange interventions, interest rate adjustments, and liquidity management are immediate responses, long-term measures such as trade reforms and incentivizing capital inflows are essential for maintaining macroeconomic stability. A calibrated and flexible policy approach, considering global uncertainties and domestic growth requirements, will be crucial in navigating this situation effectively.

प्रश्न: रुपये के अवमूल्यन से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए मुद्रास्फीति, विकास और मुद्रा स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नीति विकल्पों का विश्लेषण करें।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास और मुद्रा स्थिरता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में अहम चुनौतियां पेश करता है। कमजोर होता रुपया आयात लागत बढ़ाता है, मुद्रास्फीति को बढ़ाता है और बाहरी ऋण देश पर बोझ भी बढ़ाता है। साथ ही, यह निर्यात प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है। मौद्रिक स्थिरता के संरक्षक के रूप में RBI के पास इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कई नीतिगत विकल्प हैं।

RBI के लिए उपलब्ध नीति विकल्प

1. विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप

- **प्रत्यक्ष डॉलर बिक्री:** RBI अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बेच सकता है। उदाहरण के लिए, 2018 में, जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 के स्तर को पार कर गया, तो RBI ने मुद्रा को स्थिर करने के लिए डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया। हालांकि, बार-बार हस्तक्षेप करने से विदेशी मुद्रा भंडार कम भी हो सकता है।
- **खरीद-बिक्री स्वैप तंत्र:** सीधे डॉलर बेचने के बजाय, RBI स्वैप तंत्र का उपयोग कर सकता है, जैसा कि 2019 में देखा गया था, जब इसने रुपये को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हुए तरलता का प्रबंधन करने के लिए \$5 बिलियन की स्वैप नीलामी शुरू की थी।

2. ब्याज दर समायोजन

- **सख्त मौद्रिक नीति लागू करना:** रेपो दर बढ़ाने से विदेशी पूंजी का प्रवाह आकर्षित हो सकता है, जिससे रुपया मजबूत हो सकता है। 2013 में, 'टेपर टैटम' संकट के दौरान, RBI ने पूंजी बहिर्वाह और रुपये के मूल्यहास का मुकाबला करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं। हालांकि, उच्च दरें आर्थिक विकास को भी धीमा कर सकती हैं।
- **तटस्थ रुख बनाए रखना:** यदि आर्थिक विकास प्राथमिकता है, तो आरबीआई आक्रामक दर की वृद्धि से बच सकता है, जैसा कि 2022 में देखा गया था जब उसने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास चिंताओं के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित किया था।

3. तरलता प्रबंधन उपाय

- **खुला बाजार परिचालन (OMO):** RBI अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर OMO का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, 2018 में, RBI ने गिरते रुपये के कारण मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए OMO का उपयोग किया था।
- **आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) का समायोजन:** CRR बढ़ाने से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे तरलता भी कम हो सकती है। 2010 में, RBI ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CRR बढ़ाया, लेकिन इससे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्धता पर भी असर पड़ा था।

4. पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना

- **FDI और FPI को प्रोत्साहित करना:** प्रतिबंधों में ढील और निवेशकों के विश्वास में सुधार करके रुपये को स्थिर किया जा सकता है। 2019 में, RBI और SEBI ने FPI मानदंडों में ढील दी, जिससे निवेश आकर्षित करने और रुपये को मजबूती देने में मदद मिली।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की निगरानी:** अत्यधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार को विनियमित करने से मुद्रा के बेमेल को रोका जा सकता है। इसी के चलते 2013 में, RBI ने ECB मानदंडों को कड़ा किया था।

5. व्यापार और संरचनात्मक सुधार

- **व्यापार घाटे का प्रबंधन:** गैर-आवश्यक आयात (जैसे 2013 में सोने पर प्रतिबंध) को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना रुपये को स्थिर करने में मदद कर सकता है।
- **निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना:** 2022 में रुपये के मूल्यहास से आईटी क्षेत्र को लाभ हुआ, जिसमें इंफोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने निर्यात आय में वृद्धि के कारण उच्च राजस्व की रिपोर्ट की थी।

6. बाजार-संचालित समायोजन की अनुमति देना

- **रुपये को स्वाभाविक रूप से समायोजित करने देना:** धीरे-धीरे मूल्यहास से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, 2020 में, RBI ने निर्यात का समर्थन करने के लिए COVID-19 व्यवधानों के बीच

रुपये को मूल्यहास की अनुमति दी थी। हालाँकि, अत्यधिक मूल्यहास मुद्रास्फीति के दबाव को भी जन्म दे सकता है।

रुपये का अवमूल्यन RBI के लिए एक जटिल चुनौती पेश करता है, जिसके लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास और मुद्रा स्थिरता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। जबकि विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप, ब्याज दर समायोजन और तरलता प्रबंधन तत्काल प्रतिक्रियाएँ हैं, व्यापार सुधार और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने जैसे दीर्घकालिक उपाय व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नीति दृष्टिकोण इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।